BIHAR FOUNDATION
BONDING • BRANDING • BUSINESS

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

+91 0612 2547371
+91 85442 99526
https:// biharfoundation. bihar.govt.in

सम्प्रति बिहार

बिहार फाउन्डेशन की प्रस्तुति

बिहार के महत्वपूर्ण अखबारों में छपे **सकारात्मक** समाचारों का संकलन

ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्थी शुक्रवार विक्रम संवत् 2079। 03 जून 2022

JKDESIGN 8369994118

6TH FLOOR, INDIRA BHAWAN, RCS PATH, PATNA-800001. BIHAR, INDIA.

सूबे की 3 प्रसिद्ध मिठाइयों को मिलेगा जीआई टैग

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। कृषि उत्पादों के बाद अब राज्य की स्वादिष्ट मिठाइयों को भी ग्लोबल पहचान मिलेगी। भोजपुर के खुरमा, गया के प्रसिद्ध तिलकुट और सीतामढ़ी की बालूसाही को भी जीआई टैग दिलाने की पहल होगी। इसकी पहल नाबार्ड ने शुरू कर दी है। इसके पहले इन मिठाइयों की विशेषताओं और उनके स्रोत की जानकारी नाबार्ड लेगा। उसके बाद उत्पादकों से इसके लिए आवेदन करने को कहेगा।

नाबार्ड आवेदन से लेकर इन मिठाइयों को जीआई टैग दिलाने में भरपूर मदद करेगा। गया का तिलकुट विश्व प्रसिद्ध है। विदेशों में रहने वाले बिहारियों के माध्यम से इसको ग्लोबल पहचान मिली है। इसी के साथ सीतामढ़ी की बालूसाही और भेजपुर जिले के उदवंतनगर का खुरमा भी काफी प्रसिद्ध है। राज्य में इन मिठाइयों की पहचान ऐसी है कि जिन जिले से इनको प्रसिद्धि मिली है, राज्य में कहीं भी यह मिठाई बनती है तो उसी जिले के नाम से बिकती है। लेकिन जीआई टैग नहीं होने के कारण इनकी पहचान का प्रमाणीकरण नहीं हो पाया है। लिहाजा इनकी मांग होने के बावजूद विदेशों में नहीं बिक पाती हैं।

साथ ही कीमत भी उत्पादकों को नहीं मिल पाती है। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. सुनील कुमार ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड इन मिठाइयों को जीआई टैग दिलाने में मदद करेगा। इसका उद्देश्य है कि इसका लाभ उत्पादकों को मिले। जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर जीआई टैग के लिए उत्पादकों से आवेदन कराया जागा।

आमदनी और उत्पादन बढ़ेगा

इन मिठाइयों को जीआई टैग मिलने के बाद विश्व में कोई कहीं मार्केटिंग करेगा तो वह बिहार के उन जिलों के नाम से जाना जाएगा। दूसरे किसी भी देश और राज्य का दावा इन उत्पादों पर नहीं हो सकेगा। इसी के साथ राज्य के इन उत्पादकों को नया बाजार मिल जाएगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। उत्पादन भी बढ़ेगा। अगर इन मिठाइयों को जीआई टैग मिला तो मखाना को मिलाकर राज्य के कुल आठ उत्पादों को जीआई टैग मिल जाएगा। इसके पहले कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची और मगही पान को जीआई टैग मिल चुका है।

सौजन्य से हिन्दुस्तान | पटना | 03.06.2022 | पृष्ठ सं० 02

राज्य के 11 जिलों से होकर गुजरेगी गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे

पथ निर्माण

- दो अन्य जिले मधेपुरा और सहरसा से होकर भी एक्सप्रेस-वे को ले जाने की राज्य ने केंद्र से की मांग

संवाददाता ▷ पटना

गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे को राज्य के 11 जिलों से गुजरेगी. फिलहाल इस एक्सप्रेस-वे को नौ जिलों से होकर गुजरने की केंद्र से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है. इसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, फारबिसगंज और किशनगंज जिले शामिल थे. अब दो अन्य जिले मधेपुरा और सहरसा से होकर भी इस एक्सप्रेस-वे को ले जाने की राज्य सरकार ने केंद्र से मांग की है. इसे लेकर हाल ही में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष प्रस्ताव रखा है. इस पर केंद्रीय मंत्री ने विचार करने का आश्वासन दिया है. फिलहाल इसकी डीपीआर बन रही है और इसी साल निर्माण शुरू कर 2025 तक पूरा करने की समय-सीमा है.

इसी साल शुरू होगा सड़क निर्माण, 2025 तक हो जायेगा पूरा

इसका अधिकतर हिस्सा करीब 416 किमी की लंबाई में बिहार से होकर गुजरेगा

तीन राज्यों को जोड़ेगा एक्सप्रेस -वे

सूत्रों के अनुसार गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश से बिहार होकर सिलीगुड़ी तक पहुंचेगा. ऐसे में तीन राज्यों को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेस-वे की लंबाई करीब 600 किमी है. इसका अधिकतर हिस्सा करीब 416 किमी की लंबाई में बिहार से होकर गुजरेगा. यदि मधेपुरा और सहरसा जिलों से होकर केंद्र सरकार से मंजूरी मिली, तो इसके अलाइनमेंट में थोड़ा बदलाव हो सकता है. यह न सिर्फ बिहार को उत्तर प्रदेश और बंगाल के बीच न केवल आवागमन आसान करेगा, बल्कि व्यापार के नये रास्ते भी इससे खुलेंगे. इस एक्सप्रेस-वे का पूरा हिस्सा ग्रीनफील्ड होगा. यह भी जानकारी मिली है कि किसी पुरानी सड़क को एक्सप्रेस-वे में शामिल नहीं किया जायेगा.

पूरा हिस्सा ग्रीनफील्ड होगा

इस एक्सप्रेस-वे का पूरा हिस्सा ग्रीनफील्ड होगा. किसी पुरानी सड़क को एक्सप्रेस-वे में शामिल नहीं करने की योजना है. इस एक्सप्रेस-वे का उत्तर प्रदेश में गोरखपुर-आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेस-वे सहित अन्य सड़कों से भी जुड़ाव होगा. इस तरह सिलीगुड़ी से उत्तर प्रदेश के ग्रमुख शहरों के साथ ही दिल्ली आना-जाना आसान होगा.

दूरी घट कर 600 किमी से भी कम हो जायेगी

फिलहाल गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है. इस कारण गोरखपुर से सिलीगुड़ी की दूरी तय करने में काफी समय लग जाता है. प्रस्तावित गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे से दोनों शहरों के बीच की दूरी घटकर करीब 600 किमी से भी कम हो जायेगी. इससे आवागमन आसान होगा. साथ ही व्यापार के नये रास्ते भी खुलेंगे.

सौजन्य से प्रभात खबर | पटना | 03.06.2022 | पृष्ठ सं० 02

उत्तर बिहार के लिए बस का नया रास्ता • गांधी मैदान से डाकबंगला, जंक्शन, आर ब्लॉक, अटल पथ, गंगा पथ, जेपी सेतु के रास्ते चलेंगी

अटल पथ होते हाजीपुर के लिए 25 से चलेंगी सीएनजी बसें

पटना | अटल पथ से जेपी सेतु जाने का रास्ता बनकर तैयार हो गया है। इसलिए अटल पथ पर 25 जून से बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। परिवहन विभाग के अधिकारी के मुताबिक 70 नई सीएनजी बसें 15 जून तक आ जाएंगी। इन बसों के आने के बाद गांधी मैदान से डाकबंगला, पटना जंक्शन, आर ब्लॉक, अटल पथ, गंगा पथ, जेपी सेतु के रास्ते सोनपुर और हाजीपुर तक ट्रायल किया जाएगा। इसके बार चार सीएनजी बसों का परिचालन होगा। अभी सरकारी बसें गांधी सेतु होकर उत्तर बिहार जाती हैं। अब उत्तर बिहार जाने के लिए अटल पथ दूसरी सड़क होगी। इससे पटना, सोनपुर और हाजीपुर के 50 से अधिक मोहल्ले के लोगों को सुविधा होगी। इन मोहल्ले के लोगों को सड़क पर निकलते ही सीएनजी सिटी बस मिलेगी। अटल पथ पर आर ब्लॉक, मोहनपुर संप हाउस, महेशनगर, राजीवनगर और दीघा में बसें रुकेंगी। गांधी मैदान से अटल पथ और जेपी सेतु होते हाजीपुर स्टेशन तक सिटी बस का 15वां रूट होगा। अभी शहर में 14 रूटों पर नगर बस सेवा बहाल है।

लोकनायक गंगा पथ के गोलंबर से जुड़ गया अटल पथ

पुनाईचक फुट ओवरब्रिज पर गार्टर चढ़ा, आर ब्लॉक की ओर जाने वाली अटल पथ की लेन आज से होगी चालू

सिटी रिपोर्टर | पटना

अटल पथ पर पुनाईचक के पास बन रहे फुट ओवरब्रिज पर गार्टर चढ़ाने का काम गुरुवार को पूरा हो गया। शुक्रवार से दीघा से आर ब्लॉक की ओर जाने वाली हाईवे की लेन चालू हो जाएगी। फुट ओवरब्रिज के निर्माण के लिए इस लेन को बंद किया गया था। एक महीने से बेली रोड से आर ब्लॉक की ओर गाड़ियां सर्विस रोड से जाती थीं। बीएसआरडीसी के अधिकारियों के मुताबिक अटल पथ का यह चौथा और अंतिम फुट ओवरब्रिज इस महीने के अंततक चालू हो जाएगा। इससे पुनाईचक से बोरिंग रोड पैदल आने-जाने वाले लोगों को सुविधा होगी।

लिफ्ट चालू नहीं होने से बुजुर्ग परेशान

अटल पथ पर पैदल आर-पार होने के लिए चार फुट ओवरब्रिज बनाने की योजना थी। इनमें राजीवनगर, महेश नगर और एमएलए फ्लैट के पास फुट ओवरब्रिज का निर्माण पहले ही हो चुका है। इनपर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए दोनों तरफ लिफ्ट लगाया गया है। साउंडलेस जेनरेटर भी लगा है। लेकिन, लिफ्ट चालू नहीं होने से बुजुर्ग, बीमार, महिलाओं-बच्चों को आने-जाने में परेशानी हो रही है।

फ्लाईओवर के नीचे बाजार लगने से जाम

अटल पथ पर छह जगहों पर फ्लाईओवर बनाए गए हैं। इनमें बेली रोड, शिवपुरी, राजीवनगर, दीघा बाजार स्थित अशोक राजपथ, एफसीआई और एफसीआई डेडिकेटेड शामिल हैं। अभी शिवपुरी और राजीवनगर में सब्जी बाजार लगाने से शाम के वक्त जाम लग जाता है।

सौजन्य से दैनिक भास्कर | पटना | 03.06.2022 | पृष्ठ सं० 02

इस योजना से बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर भूभाग में सिंचाई क्षमता विकसित होगी

52 साल बाद उत्तर कोयल जलाशय योजना के निर्माण का रास्ता साफ

एक्सक्लूसिव

■ आलोक चन्द्र

पटना। लगभग पांच दशकों के बाद बिहार की महत्वाकांक्षी परियोजना उत्तर कोयल जलाशय योजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। वन विभाग की स्वीकृति न मिलने और कई तकनीकी कारणों से योजना लंबे समय से अटकी थी।

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की बैठक में 52 वर्षों से अटकी इस परियोजना को जमीन पर उतारने का रास्ता निकाल लिया गया। लगातार पहल और तकनीकी समस्याओं को दूर करने की विस्तृत कार्ययोजना ने बिहार को बड़ी सफलता दिला दी। केन्द्र की सहमति के बाद सूबे का जल संसाधन विभाग इस योजना को पूरा करने के लिए बेहद आशान्वित है। इस योजना से बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर भूभाग में सिंचाई क्षमता विकसित होगी। केन्द्रीय जल आयोग ने उत्तर कोयल जलाशय योजना के शेष कार्यों के लिए 1738 करोड़ की स्वीकृति दी है। आयोग की एडवाइजरी कमेटी के अनुसार इसमें बिहार भू-भाग में 1251 करोड़ खर्च होंगे। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने इस परियोजना के शेष कार्यों को केन्द्रीय एजेंसी वैपकॉस से कराने का निर्णय लिया गया है। केन्द्र सरकार के इस निर्णय के बाद दक्षिण बिहार के बड़े इलाके के किसानों का वर्षों का सपना पूरा होगा और पानी के लिए तरस रहे खेतों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। यही नहीं दक्षिण बिहार को सूखे की समस्या से भी निजात मिलेगी।

उत्तर कोयल से बिहार के लाभान्वित क्षेत्र

औरंगाबाद : नवीनगर, कुटुम्बा, औरंगाबाद, रफीगंज, बारुण, देव, मदनपुर, गोह

गया : आमस, गुरुआ, गुरारु, कोंच

1738
करोड़ स्वीकृत किए केंद्रीय जल आयोग की एडवाइजरी कमेटी ने

- प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की बैठक में निकला रास्ता, वैपकॉस करेगा शेष कार्य पूर्ण

- जलाशय का पूर्ण जलस्तर 367.28 मीटर से घटाकर 341.10 मीटर करने का निर्णय
- बिहार के बंटवारे के बाद अटक गयी थी योजना, झारखंड से नहीं बन पा रही थी सहमति
- बिहार की पहल और लगातार मॉनीटरिंग से आखिर निकला हल

77.70
किलोमीटर बिहार भाग में इसकी लंबाई

31.40
किलोमीटर झारखंड में है इसकी लंबाई

क्या है उत्तर कोयल जलाशय योजना

उत्तर कोयल जलाशय योजना बिहार और झारखंड की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। इसका निर्माण वर्ष 1970 में प्रारंभ किया गया था। तब इस योजना के लिए 30 करोड़ मंजूर किये गये थे। निर्माण की धीमी गति और तकनीकी कारणों से योजना में अवरोध बना रहा। इसके बाद इसकी लागत राशि बढ़ती रही। पिछले दिनों इसके छटे पुनरीक्षित प्राक्कलन को मंजूरी दी गयी। इसके तहत इस योजना पर 2391.36 करोड़ खर्च होने थे पर निर्माण पूरा नहीं होने पर अब सातवां पुनरीक्षित राशि स्वीकृत की गयी है। अब इसकी लागत 3042.16 करोड़ हो गयी है। अर्थात 52 वर्षों में लागत राशि 100 गुनी से अधिक बढ़ गयी। योजना के तहत झारखंड के पलामू जिला के कुटकु (मंडल) ग्राम में उत्तर कोयल नदी पर कंक्रीट डैम निर्मित है। इसके 96 किलोमीटर नीचे मोहम्मदगंज में 819.60 मीटर लंबा बराज बना है। यहीं नहीं उत्तर कोयल दायां मुख्य नहर की कुल लंबाई 109.10 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 77.70 किमी है।

> लंबे प्रयास के बाद बिहार को सफलता मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लगातार मार्गदर्शन और इस योजना को लेकर गंभीरता से हमारी कोशिश सफल रही। हमने इस योजना से जुड़ी तमाम समस्याओं को वन टू वन दूर किया और नतीजा सामने है। इस योजना के शेष कार्यों को केन्द्रीय एजेंसी वैपकॉस पूरा करेगी। इससे दक्षिण बिहार के बड़े इलाके में सिंचाई क्षमता का सृजन होगा।
>
> – संजय कुमार झा, जल संसाधन मंत्री

ये थी परेशानी, ऐसे निकला रास्ता

दरअसल, झारखंड स्थित बेतला राष्ट्रीय पार्क के बफर क्षेत्र के कारण वन भूमि की स्वीकृति नहीं मिलने से उत्तर कोयल जलाशय योजना का कार्य वर्षों से अवरुद्ध था। तर्क दिया गया कि डैम में फाटक लगाने से बेतला टाइगर प्रोजेक्ट का 6 हजार हेक्टेयर क्षेत्र डूब जाएगा। इससे टाइगर प्रोजेक्ट प्रभावित होगा। बिहार की पहल पर पिछले दिनों प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में वन भूमि के डूब क्षेत्र को बचाने के लिए जलाशय का पूर्ण जलस्तर (एफआरएल) 367.28 मीटर से घटाकर 341 मीटर रखने का निर्णय लिया गया। इससे बिजली उत्पादन लाभ स्वतः हट गया जबकि लाइव स्टोरेज में कमी आई। पहले एफआरएल घटाकर 363 मीटर करने की योजना बनी, लेकिन उससे समस्या का हल नहीं निकला। बाद में इसे और कम किया गया।

सौजन्य से हिन्दुस्तान | पटना | 03.06.2022 | पृष्ठ सं० 02

पटना सिटी में 10 से अधिक स्थानों पर होगी इतिहास की खोज

संवाददाता ▷ पटना

पटना सिटी में इतिहास की खोज के लिए 10 से अधिक जगहों पर खुदाई की जायेगी. आइआइटी, कानपुर की टीम पटना पहुंचने वाली है, जो 20 जून के बाद किसी भी दिन सर्वे का काम शुरू करेगी. सर्वे रिपोर्ट आने के बाद खुदाई की जायेगी. दरअसल, बिहार के विभिन्न जिलों में इतिहास छिपा हुआ है. इसकी खोज कला संस्कृति एवं युवा विभाग का पुरातात्विक निदेशालय आइआइटी, कानपुर की मदद से कर रहा है. इसकी शुरुआत बांका के भदरिया गांव से हुई है. पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना सिटी के पुराने इलाकों का भ्रमण किया था और पुरातात्विक जानकारी के लिए खुदाई का निर्देश दिया था. फिलहाल आठ जगहों का सर्वे शुरू होगा.

1. आइआइटी कानपुर की टीम करेगी सर्वे, इसके बाद शुरू होगी खुदाई
2. 20 जून के बाद शुरू होगा सर्वे, सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद शुरू होगी खुदाई

ऐसे होता है सर्वे

ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर सर्वे अत्याधुनिक तकनीक है. इसमे ऊपर की सतह की तस्वीर के लिए रडार का उपयोग होता है. इसमें बिना खुदाई कराये ही जमीन से 15 मीटर नीचे तक की जानकारी आसानी से मिल जाती है. इसमें माइक्रो लेवल तक फिल्म लेना आसान होता है.

इन जगहों का होगा सर्वे

- गुलजारबाग सरकारी प्रेस का खेल मैदान
- भद्र घाट
- महावीर घाट
- बेगम की हवेली
- बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज मैदान
- सैफ खान का मदरसा
- मंसूर मजार
- मेहंदी मजार

बांका में पूरा हुआ सर्वे जल्द आयेगी रिपोर्ट

जीपीआर सर्वे का काम बांका के अमरपुर प्रखंड के भदरिया गांव में पूरा हो गया है. अब रिपोर्ट आने के बाद बांका में खुदाई का काम होगा. विभाग के मुताबिक जुलाई से पहले बांका सर्वे की रिपोर्ट मिल जायेगा.

पटना सिटी के चिह्नित इलाकों के जीपीआर सर्वे का काम आइआइटी कानपुर की टीम जून अंत तक शुरू करेगी. इसकी तैयारी पूरी कर ली गयी है. सर्वे रिपोर्ट के बाद फिर आगे की कार्रवाई होगी.

-दीपक आनंद, अपर सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग.

सौजन्य से प्रभात खबर | पटना | 03.06.2022 | पृष्ठ सं० 03

बिहार कोविड अपडेट

⇒ कुल सक्रिय मामलों की संख्या	41
⇒ पिछले 24 घंटे के दौरान नए पॉज़िटिव मामलों की संख्या	6
⇒ पिछले 24 घंटे के दौरान स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या	6
⇒ कुल वैक्सीनेशन	13,26,24,966
⇒ कम से कम एक डोस	7,07,40,158
⇒ पूर्ण वैक्सीनेटेड	6,00,34,172

बिहार फाउन्डेशन नेटवर्क

विदेश अवस्थित चैप्टर

कतर

दक्षिण कोरिया

जापान

हॉंग कॉंग

यू.ए.ई.

सिंगापुर

बहरीन

न्यूजीलैंड

कनाडा

यू.एस.ए.

ऑस्ट्रेलिया

सऊदी अरब

देश अवस्थित चैप्टर

मुम्बई

हैदराबाद

पुणे

चेन्नई

नागपुर

गुजरात

कोलकाता

वाराणसी

गोवा

पाठकों से अपील

बिहार फाउन्डेशन के जुड़ने के लिए

बिहार फाउंडेशन उद्योग विभाग के अन्तर्गत राज्य सरकार की एक निबंधित सोसाईटी है जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के बाहर बसे देश-विदेश अवस्थित बिहारी समुदायों को उनके स्वयं के बीच तथा गृह राज्य के साथ जोड़ने का है। वर्तमान मे बिहार फाउंडेशन के कुल 21 चैप्टर्स हैं. बिहार फाउंडेशन से जुड़ने के लिए नीचे दिए वेबसाइट पर जाकर Non Resident Bihari Registration पर क्लिक करें और उपलब्ध फार्म को भरकर जमा करें -

https://biharfoundation.bihar.gov.in.